नईदुनिया

राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहारों पर लाना चाहिए श्वेतपत्र, पूर्व आरबीआई गवर्नर की केंद्र को सलाह

हैदराबाद ।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने मुफ्त उपहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सलाह दी है। उनका कहना है कि सरकार को मुफ्त उपहार देने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने के लिए श्वेत पत्र लाना चाहिए। साथ ही इस बारे में गहन बहस होनी चाहिए कि इस संबंध में राजनीतिक दलों पर कैसे अंकुश लगाया जाए।

मुफ्त उपहारों की लागत और लाभों के बारे में करें जागरूक – सुब्बाराव ने यह भी सलाह दी कि आम जनता को इन मुफ्त उपहारों की लागत और लाभों के बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस बारे में लोगों को कैसे शिक्षित करे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इस पर राजनीतिक सहमति होनी चाहिए। इसका नेतृत्व केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को करना होता है। मेरा मानना है कि उन्हें एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए।

इस पर कैसे लगा सकते हैं रोक – आरबीआई के पूर्व गवर्नर का कहना है कि लोगों को मुफ्त उपहारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस पर कैसे रोक लगा सकते हैं और हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत जैसे गरीब देश में यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सबसे कमजोर वर्गों को कुछ सुरक्षा तंत्र प्रदान करे और यह भी आत्मनिरीक्षण करे कि वित्तीय बाधाओं को देखते हुए उन्हें कितना दूर तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा, आपको पूछना चाहिए कि क्या यह इस धन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है या हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें मुफ्त उपहारों पर अधिक जागरूक होना चाहिए। साथ ही जोरदार बहस करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि हम राजनीतिक दलों पर कुछ संयम कैसे लगा सकते हैं।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी – एफआरबीएम की सीमा का उल्लंघन करने वाले कुछ राज्यों के बारे में उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहिए ।

न्यूज ब्रीफ

भारत को सतत विकास और निवेश बढ़ाने के लिए सुधार जारी रखने चाहिए, आईएमएफ अधिकारी ने दी सलाह

नई दिल्ली । आम लोगों के खर्च में इजाफा होने और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से भारत सतत विकास की राह आगे बढ़ रहा है। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की यह प्रगति बनी हुई है। आईएमएफ की एशिया पैसिफिक विभाग की निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने यह दावा किया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6.8 प्रतिशत विकास दर का आंकड़ा बहुत प्रभावी है और यह आमलोगों के बीच उपभोग और सार्वजनिक संपत्ति में सरकार की ओर से निवेश बढ़ाने के कारण है। श्रीनिवासन ने कहा कि भारत कोरोना महामारी और हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव जैसी चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने में सफल रहा है। भारत की वृद्धि क्षमता को स्वीकार करते हुए उन्होंने जनसांख्यिकीय लाभ का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए भारत में सुधारों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। भारत में हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोग श्रम बल में जुड़ सकते हैं आईएमएफ के अधिकारी ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम कानूनों और कारोबारी माहौल में महत्वपूर्ण निवेश पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है ताकि देश अपनी आर्थिक क्षमताओं को साकार कर सके। उन्होंने कहा, मैं अब इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि भारत एक युवाओं की बढ़ती आबादी वाला देश है। भारत में हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोग श्रम बल में जुड़ सकते हैं। यदि आप इस मानव संसाधन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय निवेश पर जोर देना चाहूंगा ताकि बढ़ता श्रम बल अर्थव्यवस्था में उत्पादक योगदान दे सके। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत को अपनी व्यापार व्यवस्था को भी उदार बनाने की जरूरत है ताकि पाबंदियां हटाई जा सकें ताकि कंपनियां आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकें। आपको एफडीआई के लिए माहौल को और आकर्षक बनाना होगा। श्रीनिवासन ने चीन के बराबर या उससे भी अधिक वृद्धि दर बनाए रखने के लिए भारत में सुधारों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, चीन भारत से चार गुना बड़ा है। भारत के लिए मध्यम अवधि की अच्छी संभावनाएं 6.5 प्रतिशत पर बहुत अच्छी हैं। यह उससे बेहतर कर सकता है, लेकिन इसके लिए भारत में वे सुधार होने जरूरी हैं, जिनकी देश को जरूरत है। भारत अगले कई वर्षों में 6.5 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल कर सकता है श्रीनिवास ने कहा कि भारत अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सुधारों को शुरू करता है तो अगले कई वर्षों में 6.5 प्रतिशत या उससे अधिक की जीडीपी हासिल कर सकता है। उन्होंने जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने पर चिंता भी जाहिर की।

एचडीएफसी बैंक का शुद्ध मुनाफा 34 प्रतिशत बढ़ा, ब्याज से होने वाली आमदनी में 24.5 प्रतिशत का इजाफा

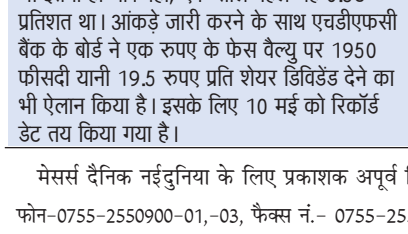

नई दिल्ली । निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता एचडीएफसी बैंक का एकल शुद्ध मुनाफा मार्च को समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 37.1 प्रतिशत बढ़कर 16,512 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। तिमाही के दौरान इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 24.5 प्रतिशत बढ़कर 29,077 करोड़ रुपये हो गई। अपने तिमाही नंबरों की घोषणा करते हुए, एचडीएफसी बैंक ने लिए प्रति शेयर 19.5 का लाभांश भी घोषित किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुल संपत्ति पर 3.44 प्रतिशत और ब्याज़ अर्निंग असेट के आधार पर 3.63 प्रतिशत रहा। एचडीएफसी बैंक ने अपनी फाइलिंग में कहा कि अर्थव्यवस्था में ऋणों का माहौल बेहतर बना हुआ है। बैंक का सभी क्षेत्रों में क्रेडिट प्रदर्शन स्वस्थ बना हुआ है। पिछले तिमाही की तुलना जीएनपीए में 1.24 प्रतिशत का सुधार हुआ है। बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उसका नेट एनपीए नेट एडवांस का 0.33 प्रतिशत रहा जो एक साल पहले 0.27 प्रतिशत और दिसंबर तिमाही में 0.31 प्रतिशत था। बैंका रिटर्न ऑन असेट्स यानी आरओए 0.49 प्रतिशत रहा जो दिसंबर तिमाही में भी इतना ही था। वहीं, एक साल पहले यह 0.53 प्रतिशत था। आंकड़े जारी करने के साथ एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने एक रुपए के फेस वैल्यु पर 1950 फीसदी यानी 19.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इसके लिए 10 मई को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है।

टॉप-10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1.40 लाख करोड़ कम हुई

टीसीएस की मार्केट-वैल्यू एक हफ्ते में 62,538 करोड़ गिरी

मुंबई।

बीते कारोबारी हफ्ते मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप-10 कंपनियों में से 6 के मार्केट कैप में कंबाइंड रूप से 1,40,478.38 करोड़ (1.40 लाख करोड़) की गिरावट आई है। इस दौरान मार्केट का सबसे बड़ा लूजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 62,538.64 करोड़ गिरकर 13.85 लाख करोड़ रह गया है। टीसीएस के अलावा इंफोसिस और आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप भी 30,488.12 करोड़ और 26,423.74 करोड़ कम हुआ है।

एयरटेल का मार्केट कैप 37,797 करोड़ बढ़ा

वहीं, टॉप-10 में केवल 4 कंपनियों ने पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की है। इनमें मार्केट की टॉप गेनर भारती एयरटेल रही है। कंपनी का मार्केट कैप एक हफ्ते में 37,797.09 करोड़ बढ़ा है। अब कंपनी का मार्केट कैप 7.31 लाख करोड़ हो गया है। एयरटेल के साथ-साथ एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एलआईसी की मार्केट वैल्यू बढ़ी है।

करीब 600 अंक तेजी के साथ बंद हुआ था बाज़ार

शेयर बाजार आखिरी कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुआ था। सेंसेक्स 599.34 अंक की तेजी के साथ 73,088.33 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 151.15 अंक की तेजी रही थी, ये 22,147 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में करीब 700 अंकों की गिरावट के बाद यह शानदार रिकवरी देखने को मिली।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही और सिर्फ 8 में गिरावट देखने को मिली। कारोबार में बैंक, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही।

मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है

मार्केट कैप किसी भी कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयरों यानी वे सभी शेयर, जो फिलहाल उसके शेयरहोल्डर्स के पास हैं, की वैल्यू है। इसका कैलकुलेशन कंपनी के जारी शेयरों की टोटस नंबर को स्टॉक की प्राइस से गुणा करके किया जाता है।

मार्केट कैप का इस्तेमाल कंपनियों के शेयरों को कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है ताकि निवेशकों को उनके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार उन्हें चुनने में मदद मिले। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां।

मार्केट कैप कैसे काम आता है

किसी कंपनी के शेयर में मुनाफा मिलेगा या नहीं इसका अनुमान कई फैक्टर्स को देख कर लगाया जाता है। इनमें से एक फैक्टर मार्केट कैप भी होता है। निवेशक मार्केट कैप को देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है।

कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होता है उसे उतनी ही अच्छी कंपनी माना जाता है। डिमांड और सप्लाई के अनुसार स्टॉक की कीमतें बढ़ती और घटती है। इसलिए मार्केट कैप उस कंपनी की पब्लिक पर्सीवड वैल्यू होती है।

मार्केट कैप कैसे घटता-बढ़ता है

मार्केट कैप के फॉर्मूले से साफ है कि कंपनी की जारी शेयरों की कुल संख्या को स्टॉक की कीमत से गुणा करके इसे निकाला जाता है। यानी अगर शेयर का भाव बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा और शेयर का भाव घटेगा तो मार्केट कैप भी घटेगा।

कर्मचारी दफ्तर में आने के बाद काम करें, किसी बात पर बहस नहीं: पिचाई

वाशिंगटन ।

बीते दिनों इजराइल के साथ काम करने के विरोध में गूगल कर्मचारियों के गिरफ्तारी के बाद कंपनी ने 28 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। जिसके बाद गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने इस पूरे घटनाक्रम के लेकर अपने कर्मचारियों के लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है। इस ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि वो दफ्तर में आने के बाद काम करें, ना कि राजनीति के चक्कर में उलझें। बीते कुछ दिनों से गूगल कंपनी में चल रहे उथल-पुथल को लेकर सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों के नाम एक संदेश लिखा है। उन्होंने अपने ब्लॉग पोस्ट में गूगल का कल्चर शुरू से खुली बातचीत को बढ़ावा देने वाला रहा है। यही एक वजह हमें बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने और अच्छे आइडियाज पर एक्शन लेने के काबिल बनाता हैं। कंपनी की अपनी कुछ पॉलिसी है जिसका पालन सभी को करना है। उन्होंने लिखा कि यहां पर बिजनेस से संबंधित काम किए जाते है इसलिए यहां पर ना तो व्यवधान पहुंचाने वाले मुद्दों को लेकर आपस में लड़ें ना ही राजनीति पर कोई चर्चा करें। बता दें कि सुंदर पिचाई के इस संदेश से पहले ऐसी ही हिदायत गूगल के हेड ऑफ सिक्योरिटी क्रिस रैको ने भी दी थी। उन्होंने भी कर्मचारियों से कहा था कि उन्हें तार्किक रहना चाहिए क्योंकि उनका हमारा लक्ष्य दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गनाइज करना और भरोसेमंद जानकारी उपलब्ध कराने वाला बने रहना है। दरअसल गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक और अमेजन डॉट कॉम ने इजराइल को एआई और क्लाउड सर्विस देने के लिए एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किया था। इसी प्रोजक्ट का नाम निम्बस है जिसको लेकर कुछ कर्मचारियों ने विरोध किया, जिसके बाद उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। ऐसे में गूगल के कर्मचारी वहां के वर्क कल्चर को लेकर सवाल कर रहे है जिसके बाद सुंदर पिचाई ने ब्लॉग पोस्ट लिखा।

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटैल को बोर्ड से मिली डिमर्जर की मंजूरी

मुंबई ।

आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल कारोबार को अलग करने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि उसकी योजना कंपनी के अलग होने के 12 महीनों के भीतर 2,500 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की है।

बयान के अनुसार एबीएफआरएल के निदेशक मंडल ने हाल ही में हुई बैठक में आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स लिमिटेड (एबीएलबीएल) के अलग होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

विभाजित होने की प्रक्रिया पूरी होने पर एबीएलबीएल अलग से सूचीबद्ध होगी। एबीएफआरएल ने कहा कि इस प्रक्रिया को एनसीएलटी व्यवस्था योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा और इसके पूरा होने पर एबीएफआरएल के सभी शेयरधारकों के पास दोनों कंपनियों में समान शेयरधारिता होगी। कंपनी ने बयान में कहा कि प्रक्रिया के पूरा होने के 12 महीनों के भीतर एबीएफआरएल ने अपने

बहीखाते को मजबूत करने और शेष इकाइयों की वृद्धि को जरूरी कोष उपलब्ध कराने के लिए 2,500 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की योजना बनाई है।

मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल व्यवसाय में चार फास्ट फैशन ब्रांड लुई फिलिप, वैन ह्यूसेन, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड के साथ-साथ अमेरिकन ईगल और फॉरएवर 21 जैसे कैजुअल वियर ब्रांड शामिल हैं। इसके पास स्पोर्ट्सवियर ब्रांड रीबॉक और वैन ह्यूसेन के तहत इनरवियर व्यवसाय के लिए एक ब्रांड लाइसेंस भी है, जिसे एक अलग सूचीबद्ध इकाई में विभाजित किया जाएगा।

बच्चों का सामान बनाने वाली इस कंपनी पर लगा करोड़ों का जुर्माना, कैंसर होने से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली ।

अदालत ने जे एंड जे और केन्व्यू पर 45 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। एक महिला के मुकदमा दायर करने के बाद चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि कंपनी के बेचे गए टेल्कम बेबी पाउडर में एस्बेस्टर था। जो कि महिला के कैंसर और मौत का कारण बना था।

जॉनसन एंड जॉनसन और केन्व्यू कंपनी जो बच्चों से जुड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए चर्चित है। अमूमन हर किसी के घर में जे एंड जे कंपनी के प्रोडक्ट मिल देखने मिलेंगे। लेकिन एक महिला ने अदालत में केस दायर किया है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनके परिवार के सदस्य को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हुई, जिससे उनकी मौत हो गई थी। कंपनी के बेचे गए टेल्कम

पाउडर में एस्बेस्टस था। वहीं एस्बेस्टस जो कि मेसोथेलियोमा के पैदा होने का कारण है।

परिवार ने आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था कि थेरेसा गार्सिया की मौत का जिम्मेदार दोनों कंपनियों को ठहराया था। गार्सिया की बेटी स्टेफनी साल्सेडो ने अपने परिवार की ओर से मामला दायर किया। परिवारजनों का मानना है कि 2020 में महिला की मौत कैंसर के कारण हुई। लेकिन कैंसर एस्बेस्टस के कारण हुआ। परिवारजन का आरोप था कि कंपनी ने यह जानकर भी टेल्कम पाउडर बेच दिया, जब उनको पता था कि टेल्कम पाउडर में एस्बेस्टस था। वहीं जे एंड जे का कहना है कि उसके टैल्क-आधारित उत्पादों से कैंसर नहीं होता है।

मामले की सुनवाई शुक्रवार देर रात शिकागो में हुई थी। इसमें ज्यूरी सदस्यों ने कंपनी को 45 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया, जो कि पीडिता के परिवार को दिया जाना है।

परिवार की वकील जेसिका डीन ने कहा कि परिवार आभारी है कि जूरी सदस्यों ने जे एंड जे और केनव्यू द्वारा दिए गए धोखे को देखा। और माना कि टेल्कम पाउडर कैंसर का कारण बन सकता है।

कंपनियों को पता था कि टेल्कम में एस्बेस्टस की अशुद्धियाँ हैं उसके बाद भी उस बेबी पाउडर को जे एंड जे की बोतलों में डाला गया था। वहीं परिवार ने दावा किया था कि महिला को 2016 में डिम्बग्रंथि कैंसर एस्बेस्टस से दूषित बेबी पाउडर के उपयोग के कारण हुआ था।

रुपया ही नहीं अन्य करेंसी भी... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया रुपये की कमजोरी का कारण

नई दिल्ली ।

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात के अहमदाबाद में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था और डॉलर की स्थिति मजबूत होती है, तो उसके मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव आता है। वित्त मंत्री ने कहा, इसके विपरीत, येन और यूरो के मुकाबले रुपया; हमारी आर्थिक स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रास्फीति, और आर्थिक मजबूती को देखते हुए स्थिर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, न सिर्फ रुपया बल्कि अन्य मुद्राओं में उतार-चढ़ाव और अधिक है। वैश्विक परिवेश में अनिश्चितता बढ़ रही है। ईरान और इस्त्राइल के बीच तनाव बढ़ने से पश्चिम एशिया में चुनौतीपूर्ण हालात बने हैं। यही वह क्षेत्र है जहां से सिर्फ हमारी ही नहीं पूरी दुनिया का क्रूड ऑयल निकलता है, इससे ग्लोबल इकोनॉमी में उतार-चढ़ाव बढ़ा है।

भारत को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने की हो रही कोशिश अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की ओर से अपनी भारत यात्रा स्थगित करने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने भारत को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए नीतियां तैयार की हैं और इसका मकसद न केवल घरेलू बाजार बल्कि निर्यात के लिए भी उत्पादन करना है। उन्होंने कहा, निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं। हम चाहते हैं कि विनिर्माता और निवेशक यहां आएं और न केवल भारत के लिए नहीं बल्कि निर्यात के लिए भी उत्पादन करें। हम नीतियों के जरिये विनिर्माणकर्ताओं और निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। टेस्ला के सीईओ मस्क ने कहा कि कंपनी की भारी जिम्मेदारियों के कारण उनकी भारत यात्रा में देरी हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा, जब बड़ी कंपनियां भारत आने में दिलचस्पी दिखाएंगी तो हम उनके लिए यहां आकर निवेश करना आकर्षक बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। उस प्रक्रिया में, यदि चर्चा करने के लिए कुछ है, तो हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन हमने जो कुछ किया है, उसे नीतियों के तहत से किया है। उन्होंने कहा कि जब चीन प्लस वन कई उद्योग विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बना तो केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से मदद मिली। उन्होंने कहा कि नीतियों को इस तरह से तैयार किया गया जिससे भारत को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए एक आकर्षक स्थान बनाया जा सके। मोदी सरकार के दौरान एक महीने को छोड़कर कभी महंगाई ने टॉलरेंस बैंड के पार नहीं गई महंगाई पर वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान एक महीने को छोड़कर कभी भी महंगाई ने टॉलरेंस की बैंड की ऊपरी सीमा को पार नहीं किया जबकि उससे पहले (2014 से पहले) अर्थव्यवस्था बुरी हालत में थी और महंगाई दहाई अंक में थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उस समय (2014 से पहले) किसी को देश से कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत कठिन परिश्रम के बाद, हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम अगले दो से ढाई साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देश में रोजगार के मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कही यह बात रोजगार के मुद्दे पर सीतारमण ने कहा कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों से सटीक आंकड़ों का अभाव है लेकिन केंद्र की पहल से लाखों नौकरियां सुनिश्चित हुई हैं। उन्होंने कहा, डेटा अपर्याप्त है। मैं इस पर गर्व नहीं कह रही हूं बल्कि इसकी कमजोरी को स्वीकार करते हुए यह कह रही हूं। रोजगार के बारे में मैं इतना ही कह सकती हूं कि लोगों और स्टार्टअप्स को अलग-अलग योजनाओं के जरिए जो पैसा (करोड़ों में) दिया गया है... लोगों को उससे मदद मिली है। अक्टूबर 2022 से नवंबर 2023 के बीच रोजगार मेलों के जरिए मोदी सरकार ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। बड़ी कंपनियों को माल या सेवाएं प्राप्त करने के 45 दिनों के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भुगतान करने के नियम के बारे में पूछे जाने पर, सीतारमण ने कहा कि यह कानून 2007-08 से अस्तित्व में है और नया नहीं है। इससे पहले उन्होंने विकसित भारत-2047 विषय पर गुजरात के उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) के तहत कुल पूंजी का 28 प्रतिशत इस राज्य में आया है, राज्य ने पिछले 10-12 वर्षों में उल्लेखनीय सतर्कता दिखाई है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण गुजरात में पहले स्थान पर आता है, जिसके पास विकसित भारत 2047 के लिए विनिर्माण की सरकारी नीति और पारिस्थितिकी तंत्र तैयार है। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी गुजरात में सेवाओं के विकास के लिए एक बड़ा प्रवेश द्वार है। उन्होंने यह भी कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई आकर्षित करने में भी गुजरात तीसरे स्थान पर है।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। * फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017